को वारंट वैधता में कमी करने अस्वीकृत सामग्री के लिये अलग मांग नोट भेजने भंडार खाते के सरलीकरण उपरिशीर्षों के पुनर्वर्गीकरण आदि से संबंधित कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । इस रिपोर्ट में कई अन्य सिफारिशें शामिल हैं जिनकी गहरी संवीक्षा किये जाने की आवश्यकता है । इसके लिये एक कार्यबल गठित किया गया है ।

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज को आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा सिविल बाजार में विविधीकरण के लिये अध्ययन करने एवं योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था । उनकी रिपोर्टों में गैर-रक्षा ग्राहकों के लिये कुछ उन उत्पादों की पहचान की गई है जिनका निर्माण अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग करके किया जा सकता है । इन मदों में आटोमोबाइल उद्योग, बिजली, क्षेत्र, चीनी उद्योग आदि से संबंधित मदें शामिल हैं । संबद्ध उद्योगों से कुछ मदों के लिये आर्डर प्राप्त हुये हैं । टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज के सुझाव पर पांच क्षेत्रीय विपणन केन्द्र खोले गये हैं ताकि गैर-रक्षा ग्राहकों को की जाने वाली बिक्री में वृद्धि की जा सके । पिछले कुछ वर्षों में आयुध निर्माणी बोर्ड की विविधीकरण की दशा में हुई प्रगति काफी अच्छी है और वर्ष 1993–94 में गैर-रक्षा ग्राहकों को की गई बिक्री लगभग 21 प्रतिशत रही है ।

Joint production of a family car by Benz and TELCO

*75. SHRI V- HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a.) whether Daimler Benz is planning production of a family car with TELCO;

(b) if so, the estimated cost of the car and exact amount of investment expected to flow for the purpose in India during the next two years;

(c) whether the cost of the car is reasonable in comparison to Maruti car, and

(d) if so, how many such cars are expected to be manufactured by the private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) TELCO have recently entered into a joint venture with M/s. Daimler Benz for manufacture of 'E' class Mercedes cars in India. Government is not aware of any other proposal front M/s. Daimler Benz for manufacture of any other type of car with TELCO. Manufacture of cars is presently delicensed and therefore does not require approval of Government.

(b) to (d) Do not arise.

औद्योगिक विकास केन्द्रों को मान्यता

*76. प्रो० राम बक्ष सिंह वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए गए औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आगामी एक वर्ष के दौरान कितने केन्द्रों को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में भी औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उद्योगों का क्षेत्रीय छितराव करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पूरे देश में 70 विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 1988 में एक योजना घोषित की थी । अब तक 69 केन्द्रों का पता लगाया